सरोकारों से साक्षात्कार

रीजनल रिपोर्टर

पृष्ठ : 04
स्थापित : 2008
संस्थापक: स्व. बी. शंकर
25 जुलाई 2025, शुक्रवार
संपादक: गंगा असनोड़ा: 9412079290

श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड से प्रकाशित, साप्ताहिक आर.एन.आई.नं: UTTHIN/2008/24749, वर्ष: 17, अंक: 06, मूल्य: 10

राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे सेंट थेरेसा के 43 विद्यार्थी

गंगा असनोड़ा

सेंट थेरेसा स्कूल, श्रीनगर के 43 खिलाड़ियों का अंडर 19 कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो एवं हैंडबॉल में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए चयन हुआ है। इसमें कबड्डी बालक वर्ग में चार खिलाड़ियों, वॉलीबॉल बालक वर्ग में दो खिलाड़ियों, खो-खो बालिका वर्ग के लिए 12 खिलाड़ियों तथा हैंडबॉल बालक एवं बालिका वर्ग में 12-12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। विद्यालय की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने खुशी प्रकट की है।

विद्यालय प्रबंधक फादर जॉनसन ने सभी खिलाड़ियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, कोचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन और विद्यालय के समर्पण का परिणाम है।

विद्यालय की प्रधानाचार्या सिस्टर एनसी उक्केन ने कहा कि यह विद्यालय ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है।

इन विद्यार्थियों का हुआ राष्ट्रीय खेलों के लिए चयन

कबड्डी अंडर-19 बालक वर्ग में भार्गव नौटियाल, अंशुल पंत, दक्ष पंवार, मयंक रावत ने, वॉलीबॉल अंडर-19 बालक वर्ग में आरुष नेगी व सार्थक रावत ने, खो-खो (अंडर-19 बालिका) वर्ग में अनुष्का असवाल, कृतिका काला, आंशिक डिमरी, कुमकुम लिंगवाल, तनिषा, दीप्ति पंवार, पायल भंडारी, शुभांशी नौटियाल, सौम्या बिष्ट, संस्कृति लखेड़ा, प्रियांशी रावत, कृतिका बिष्ट ने राष्ट्रीय खेलों में जगह बनाई है।

हैंडबॉल अंडर-19 बालक वर्ग में अक्षित बिष्ट, करण जोशी, अर्पित गैरोला, अभिसार पंवार, दिव्यांशु भट्ट, सुमित उनियाल, सुशांत बिष्ट, शौर्य रावत, हर्षित दान, मनीष रुढ़ियाल, देवांश बडोनी, समृद्धि शाह, जबकि बालिका वर्ग में ऋषिका, आकृति पुंडीर, कार्तिक काला, श्रेष्ठा बडोनी, अविका सडाना, आनंदा श्री नौटियाल, शुभांशी नौटियाल, जिया बिष्ट, आंशिक डिमरी, अनुष्का रौतेला, प्रियांशी रावत, रिया ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार की है।

विद्यालय की खेल शिक्षक रीना भंडारी एवं विकास घिल्डियाल ने खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण की सराहना की। ■■■

गढ़वाल विवि के कुलपति प्रो.श्रीप्रकाश सिंह ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से की भेंट

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि के कुलपति प्रो.श्रीप्रकाश सिंह ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में शिष्टचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ और उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रुद्रनाथ की तस्वीर भेंट कर कई अहम विषयों पर चर्चा की।

प्रो.सिंह ने महामहिम को विवि में आरंभ हो रहे नवीन शैक्षणिक सत्र की तैयारियों और अध्यापन कार्य की रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विवि में पूरी तरह से लागू किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत लचीले पाठ्यक्रम, अंतरविषयीय अध्ययन और व्यावसायिक कौशलों का समावेश सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने राष्ट्रपति से चर्चा की कि विवि ने एक वेलनेस सेंटर स्थापित करने की कल्पना की है जिससे आगंतुकों के लिए पर्वतीय संसाधनों पर आधारित स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है और जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेगें। वहीं इससे पारंपरिक चिकित्सा, योग, जड़ी बूटी आधारित उत्पादों और प्राकृतिक उपचारों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। वहीं उन्होंने उत्तराखंड की सामाजिक-सांस्कृतिक सैनिक पृष्ठभूमि के मध्यनजर विवि में अग्निवीरों के लिए एक विशेष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की जानकारी दी।

राष्ट्रपति ने कहा - विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हों पूर्ण महामहिम राष्ट्रपति ने विवि के प्रयासों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि शिक्षक, विद्यार्थी और शोधार्थी गांवों में जाकर स्थानीय लोगों के साथ समय बिताएं, उनके जीवन, आवश्यकताओं और अनुभवों को समझें। इससे जब वे भविष्य में सरकारी सेवा या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत होंगे, तो उन्हें पलायन जैसी समस्याओं और ग्रामीण वास्तविकताओं की गहरी समझ होगी, जो उन्हें संवेदनशील और प्रभावी नेतृत्य प्रदान करने में सहायक होगी। ■■■

प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी बनें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नए कुलपति

उत्तराखण्ड मुक्त विवि को नया कुलपति मिल गया है। विवि की परिनियमावली 2009 के परिनियम-4 के अंतर्गत गठित अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल से प्रो. नवीन चन्द्र लोहनी का चयन किया गया है। प्रो. लोहनी वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (यूपी) में हिन्दी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रो. लोहनी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी तीन वर्षो अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उत्तराखण्ड मुक्त विवि, हल्द्वानी के कुलपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

विवि प्रशासन और शिक्षकों ने उनके नियुक्ति पर प्रसन्नता जाहिर की है और उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में विवि नई ऊंचाइयों को छुएगा। ■■■

27 प्रतिभागियों ने रामलीला के लिए ऑडिशन में किया प्रतिभाग

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

श्रीनगर गढ़वाल में एक सौ छब्बीसवें वर्ष में पहुंच रही रामलीला के मंचन के लिए रामलीला कमेटी ने कई महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष पात्रों को ऑडिशन से चयनित किए जाने के साथ ही संगीत पक्ष को मजबूत करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।

रामलीला मैदान में इसके लिए आयोजित पहले ऑडिशन में 27 प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन से रामलीला कमेटी के सदस्यों तथा उपस्थित दर्शकों को मन मोहा।

रामलीला मैदान में रामलीला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य एवं कलाकार प्रहलाद भट्ट, भुवन उनियाल, वर्तमान अध्यक्ष देवेन्द्रमणि मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष हिमांशु अग्रवाल, संजय गुप्ता, प्रवीण अग्रवाल, संगीत निर्देशक वीरेन्द्र रतूड़ी, गायिका प्रिया ठक्कर, वसुधा गौतम, वादक जगमोहन, व्यापार संघ अध्यक्ष दिनेश असवाल, रामलीला के कलाकार सुदेश जुगराण, सुधीर डंगवाल, आशीष उनियाल, भानेश असवाल, दीपक उनियाल, रो. मनीष कोठियाल, प्रियवर्त जोशी तथा बड़ी संख्या में पहुंचे अन्य दर्शकों की उपस्थिति में रामलीला कमेटी ने रामलीला के लिए ऑडिशन किया।

इस अवसर पर 27 प्रतिभागियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रामलीला के विभिन्न पात्रों का शानदार अभिनय किया। ऑडिशन में सीमा कण्डारी ने शबरी, प्रियंका बर्त्वाल ने कैकयी-शूर्पणखा, शेखर नेगी ने राम-शूर्पणखा, अनमोल काला ने राम, गीता नेगी, सुनीता कुंवर, भूमिका ने कौशल्या, संदीप मंमगाई ने भरत-शत्रुघ्न, संतोष सती, आशुतोष कुकरेती ने भरत, कुमुद रावत ने सीता, प्रियांशी ने पार्वती, अभय ठाकुर, सानिध्य भट्ट ने शत्रुघ्न, विनायक अग्रवाल ने सुग्रीव-हनुमान, आरूषी डोभाल ने अहल्या, दिव्यांश डंगवाल ने डायलॉग, हर्षित पुरोहित ने डायलॉग, गौतम डुकलान ने डायलॉग, धीरज पोखरियाल ने डायलॉग, संस्कृत विद्यालय, कन्हैया थपलियाल, आयुष बहुगुणा, राघव भट्ट, पवन जोशी, सूर्याश किमोठी, विमल प्रतिभागियों ने अन्य किरदारों के लिए ऑडिशन दिए। इस मौके पर मीडिया प्रभारी मनीष बडोनी उपस्थित रहे। ■■■

आपदा की स्थिति में होगा पुनर्मतदान

अभिषेक रावत

प्रदेश में आपदा की स्थिति में मतदान की तिथियों में परिवर्तन किया जाएगा। इसके तहत चमोली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इसके तहत मतदान क्षेत्र में आपदा, भारी वर्षा, भूस्खलन या किसी अन्य प्राकृतिक अथवा मानवीय कारण से निर्धारित तिथि को मतदान करवाना संभव न होने की स्थिति में, ऐसे मतदान केंद्रों पर पुन: मतदान कराया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आपदा के चलते मतदान न होने पर प्रथम चरण का मतदान पूर्व निर्धारित तिथि 24 जुलाई को न होने की स्थिति में पुन: मतदान 28 जुलाई, को कराया जाएगा।

द्वितीय चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि 28 जुलाई को मतदान बाधित होने पर पुन: मतदान 30 जुलाई को करवाया जाएगा। पुन: मतदान का समय प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा।

आयोग की ओर से मौसम की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने और भारी वर्षा और आपदा की संभावना वाले क्षेत्रों की शीघ्र पहचान कर वहाँ पुन: मतदान की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका-2025 के अध्याय 14 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आपदा जैसी स्थिति में पुनर्मतदान कराया जाना अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी और नामित प्रेक्षक मतदान दिवस पर मतदान स्थलों का निरीक्षण करेंगे। वे शाम तक अपनी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, जिसके आधार पर तय होगा कि किस क्षेत्र में पुनर्मतदान की आवश्यकता है। ■■■

SUBSCRIBE

संपादकीय

ग्राम स्वराज को मुँह चिढ़ाता चुनाव

उत्तराखांड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया है, जिसमें कुल 59.50 प्रतिशत मतदान हुआ। यह मतदान पिछले मतदान से पांच प्रतिशत कम था।

अखबारों और सोशल मीडिया पर तमाम जगह से आई खबरों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस मतदान में भी अधिसंख्य मतदाता नगर पंचायतों, नगर निगमों, देहरादून, दिल्ली, हल्द्वानी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, चंडीगढ़ तथा कई अन्य शहरों से खेप में अपने-अपने गांवों में पहुंचे और कोई उसी दिन तो कोई दूसरे दिन गांवों से निकल गए। इनमें से कई तो प्रत्याशी भी थे।

उत्तराखंड के पंचायत चुनाव इस बार इस मायने में अधिक महत्त्वपूर्ण रहे कि पहले ही छह माह देरी से हो रहे चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर से लेकर मतदाताओं तथा प्रत्याशियों के दो-दो मतदाता सूचियों में नाम होने को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हद तो तब हो गई, जब टिहरी क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान की सीट पर सीता देवी द्वारा अपने सभी दस्तावेज सीता देवी के नाम पर जमा करने के बावजूद प्रत्याशी का नाम सीमा देवी दर्ज कर नामांकन खारिज कर दिया गया तथा दूसरे प्रत्याशी को निर्विरोध जीता हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अपने साथ हुए अन्याय की गुहार लेकर सीता देवी उच्च न्यायालय नैनीताल पहुंची, जहां न्यायालय ने इस सीट पर दुबारा चुनाव करने का आदेश दिया। अब निर्विरोध जीत चुकी प्रत्याशी सरिता नकोटी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखने का निर्णय सुनाया। इन सभी मामलों में राज्य सरकार तथा चुनाव आयोग की वास्तविकता भी सार्वजनिक हुई है।

अल्मोड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालय ऊंचावाहन का वाइरल वीडियो मतदान केंद्रों की स्थिति बतलाने के लिए काफी है। इस मामले में अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय का बयान और अधिक निंदनीय है कि उन्होंने ऊंचावाहन में चुनाव ड्यूटी के लिए भेजे गए शिक्षक पर ही गाज गिराने की बात कही, जबकि उस विद्यालय में चुनावकर्मियों की व्यवस्था करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाही की जानी चाहिए थी। वह वीडियो इस प्रदेश में अभी भी जर्जर और बेपरवाहगी के साथ चल रहे विद्यालयों की स्थिति को भी बयां करता है, जबकि स्वयं शिक्षा मंत्री आए दिन साक्षात्कारों में यह जताना नहीं भूलते कि वे इस प्रदेश के नौनिहालों और बेरोजगारों को मुफ्त में क्या-क्या बांट रहे हैं। फेसबुक पर उनकी वायरल हो रही रील उनके इस उपकार को बखूबी उगल रही है। यूं तो मंत्रीजी को भी यह समझना चाहिए कि जो भी वे इन बच्चों, बेरोजगारों और अपने शिक्षकों को मुफ्त दे रहे हैं, वह इस देश के संविधान की बदौलत दे रहे हैं। उसी संविधान, जिसके कारण वे स्वयं मंत्री का ताज पहने हुए हैं। ■■■

जस्टिस वर्मा केस: माई लॉर्ड हाजिर हो!

रमनकृष्ण किमोठी

बस एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्तां करने को, जब हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा!

भ्रष्टाचार शब्द ये तो अब भारतीयों के जीवन में अनुराग से शामिल हो चुका है। करोड़ों-अरबों के घोटाले की सूचना जब अखबारों, सोशल मीडिया या किसी टीवी चौनल से मिलती है, तो कुछ देर के लिए अचंभित होकर कुछ पलों में ही हम भूल जाते हैं।

सहसा भारतीय समाज किसी भ्रष्टाचार में बड़ी रकम को सुन उस मंद मुस्कान को दिखाता है, जैसे मानो भ्रष्टाचारी की क्षमताओं पर अभूतपूर्व गर्व महसूस कर रहा हो, वहीं जब कभी कोई छोटे रकम की हेराफेरी नजर में आती है, तो एक हताशा में दिखाई देते हैं। मानो कह रहे हां- बड़ा निराश किया आपने, ये भी कोई चोरी हुई?

अपने सामाजिक पतन की इस गहराई को छू चुका यह समाज भी जब कभी अपनी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की खबर सुनता है, तो मानो उसकी वर्षों पहले की कुंभकर्णी नींद में सो चुकी आत्मा जैसे जाग जाती है और माथे पर भी चिंता की रेखाएं खिंच जाती हैं।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के प्रकरण को ही ले लें। मामले में न्यायपालिका की छवि धूमिल होता देख उच्चतम न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से माई लॉर्ड वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया, परंतु न्याय की यह कार्यवाही ना तो किसी विधि विशेषज्ञ के गले उतरी और ना ही आम जनता के।

सभी की उत्कंठाओं को समाप्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सील नागू के नेतृत्व में तीन सदस्य इन हाउस जांच समिति को मामले की जांच के आदेश दिए।

समिति द्वारा 53 लोगों से की गई पूछताछ के बाद न्यायाधीश वर्मा को संदिग्ध पाते हुए रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दी गई है। वह तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इसकी सूचना राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजते हुए निष्कासन की अनुशंसा कर दी और इसके साथ ही गेंद संसद के पाले में आ गई।

दरअसल भारतीय गणराज्य में न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के समन्वय पर आधारित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4),(5), अनुच्छेद 218 व न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, जहां इसकी शक्ति संसद के दोनों सदनों को दी गई है। इसके तहत न्यायाधीश के निष्कासन की कार्यवाही लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, जो कि पांच चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण-यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव आता है, तो प्रस्ताव पर कम से कम 100 सांसदों का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो वहीं राज्यसभा के लिए यह 50 सांसद हैं।

दूसरे चरण में यह अध्यक्ष (लोकसभा)/सभापति (राज्यसभा) के विवेक पर आधारित होता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या ना करें। यदि वह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, तो कार्यवाही रुक जाती है, परंतु यदि वे इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रस्ताव अपने तीसरे चरण में जाता है, जहां एक तीन सदस्य जांच समिति (सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ,एक अनुभवी न्यायविद्) न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा व प्रकरण की सच्चाई की जांच करते हैं।

इसके बाद ही चौथे चरण की शुरुआत होती है, जहां दोनों सदनों से प्रस्ताव को 2/3 के विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित करवाया जाता है। ऐसा होते ही जांच अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, जहां राष्ट्रपति न्यायाधीश के निष्कासन का आदेश जारी करते हैं और न्यायाधीश का निष्कासन पूर्ण मान लिया जाता है। ■■■

यह कैसा महिला सशक्तिकरण

पंकज मेंदोली

मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीटों की हालत सबसे खराब...चुनाव आयोग संज्ञान लें

चुनाव में महिलाओं को सीट आरक्षित कर देना अगर सशक्तिकरण माना जा रहा है, तो उनके पोस्टरों में उनकी तस्वीरें नदारद क्यों हैं। विकासनगर से देहरादून की ओर लौटते वक्त सड़क किनारे लगे चुनावी बैनरों पर नजर गई, तो हैरानी हुई। जिन सीटों पर महिलाएं प्रत्याशी हैं, वहां पोस्टरों पर उनके पति या किसी पुरुष संबंधी की तस्वीरें प्रमुखता से लगी हैं, लेकिन स्वयं महिला प्रत्याशी की तस्वीर या नाम तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा।

सबसे चिंताजनक स्थिति तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दिखी। यहाँ कई जगहों पर महिला प्रत्याशियों की तस्वीर तो दूर, नाम तक ठीक से नहीं दर्शाया गया है। पूरा प्रचार, पूरा विमर्श एक पुरुष के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है जबकि टिकट महिला को दिया गया है। क्या यह धर्म और परंपरा के नाम पर महिलाओं को राजनीतिक पहचान से दूर रखने की चाल है क्या महिलाओं को केवल आरक्षित सीटों की खानापूर्ति के लिए खड़ा किया जा रहा है

क्या यह महिला सशक्तिकरण है? जब महिला स्वयं अपनी पहचान से चुनाव नहीं लड़ पा रही, तो भविष्य में जनता का प्रतिनिधित्व किस नाम पर और किस सोच से करेगी यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न है।

चुनाव आयोग को इस प्रवृत्ति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। केवल आरक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्याशी की असल पहचान और भागीदारी भी दिखनी चाहिए।। ■■■

वो एक पल

शिवानन्द खंडूडी

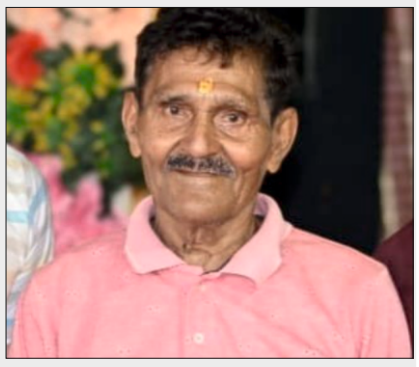

हम आ रहे थे, वो जा रहे थे...
जब उन्होंने हमें गुस्से की नजर से देखा,
तो ऐसा लगा जैसे कोई बिजली भीतर गिर पड़ी हो -
हमने अपना दिल थाम लिया,

जब हमने उन्हें प्यार की नजर से देखा,
और उन्होंने अपने नाजुक हाथों से हमें थाम लिया...
जैसे कह रही हों-
"मैं नाराज थी, पर तुमसे दूर नहीं।"

पर उस नजर के पीछे
शब्दों की एक चुप सी दीवार थी-
जिस पर न तारीख लिखी थी, न ठिकाना।
बस इंतजार की दरारें थीं।

वो जानती थीं-
मैं लौट तो आया हूँ,
पर मेरा कुछ हिस्सा अब भी
सीमा की मिट्टी में दफन है।

उन्हें पता था-
जब मैंने विदा ली थी,
तब सिर्फ उनका हाथ नहीं,
मैंने अपना घर, अपना नाम और अपना आराम भी छोड़ा था।

वो गुस्सा
कभी इस बात पर था कि
"तुम हमेशा देश को चुनते हो,"
पर वो प्यार
इसलिए जिंदा था,
क्योंकि उन्होंने कभी उसे रोका नहीं।

और आज-
जब उनके नाजुक हाथों ने
मुझे थामा,
तो वो सिर्फ प्रेमिका का स्पर्श नहीं था,
वो भारत माँ की चुप स्वीकार्यता भी थी।
जो जब प्रेम में झुका, तो मातृभूमि भी मुस्कुरा उठी। ■■■

आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है।
अपनी प्रतिक्रिया इस पते पर भेजें।
9412079290, 7037548484
regionalreporter81@gmail.com

श्री कम्यूनिकेशन के लिए गंगा असनोड़ा थपलियाल द्वारा 15 फालतू लाईन, समय साक्ष्य देहरादून से मुद्रित एवं 76, अपर बाजार श्रीनगर से प्रकाशित।
न्यायिक क्षेत्र : श्रीनगर गढ़वाल
संस्थापक संपादक : स्व. बी. शंकर
सलाहकार: वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली
संपादक : गंगा असनोड़ा थपलियाल
विशेष प्रतिनिधि : उमा घिल्डियाल
स्टेट ब्यूरो : भारती जोशी
विशेष प्रतिनिधि (गैरसैण) :
भैरव दत्त असनोड़ा

कार्यालय : श्री कम्यूनिकोशन 76, अपर बाजार, श्रीनगर गढ़वाल-246174
आर.एन.आई.न.-
UPHIN/1999/863

गढ़वाल विवि: एनईपी-2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण हेतु कार्यशाला सम्पन्न

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर स्थित ए.सी.एल. सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से आरंभ होने वाले चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

इस कार्यशाला में विज्ञान, भू-विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, कला-भाषा, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन अध्ययन विभागों के डीन, विभागाध्यक्ष और पाठ्यक्रम निर्माण में शामिल शिक्षकों ने भाग लिया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक सदस्य चाहे वह शिक्षक हों, प्रशासक या छात्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम गुणवत्तापरक शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति को संस्थागत रूप दें, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक रैंकिंग और प्रतिष्ठा में निरंतर सुधार हो सके वहीं उन्होंने सभी विभागों से अपने-अपने पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित कम से कम एक प्रश्नपत्र शामिल करने का सुझाव दिया गया।

एनईपी के विश्वविद्यालय सम्नवयक प्रो.प्रशान्त कण्डारी ने नवाचारपूर्ण पाठ्यक्रम ढाँचे, बहु-विषयक ष्टिकोण तथा छात्रों की संपूर्ण प्रतिभा-विकास के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि एनईपी 2020 के अधिकांश पाठ्यक्रम बन चुके हैं लेकिन उसमें आए कुछ बदलाव और शेष पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी देना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है।

कार्यशाला में शिक्षकों ने न केवल चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की संरचना को समझा, बल्कि इसके सफल क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव और अनुभव भी साझा किए।इस अवसर पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो ओ.पी. गुसाई, संकायध्यक्ष प्रो हरभजन चौहान, प्रो मंजुला राणा समेत सभी संकायध्यक्ष, विभागाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। ■■■

प्रख्यात कथक नर्तक आशीष सिंह ने शैम्फोर्ड फ्यूचरिस्टिक में दिया प्रशिक्षण

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

शैम्फोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल श्रीनगर ने कथक नृत्य पर एक दिवसीय कार्यशाला में कथक के प्रख्यात नर्तक आशीष सिंह (मंजरी दास) ने विद्यार्थियों के समक्ष शानदार प्रस्तुतियां दी।

इस मौके पर नर्तक आशीष सिंह ने कथक की बारीक जानकारियां भी विद्यार्थियों के साथ बांटी। शास्त्रीय नृत्य के प्रति रूझान रखने वाले विद्यार्थियों ने इस संदर्भ में उनसे सवाल भी किए। कथक नर्तक आशीष सिंह ने बताया कि उन्होंने वाराणसी में इस नृत्य शैली को समझा और इसका ज्ञान हासिल किया।

कार्यशाला में नन्हें विद्यार्थियों ने कथक की भाव-भंगिमाओं के साथ नृत्य भी किया। ■■■

नवम्बर 2025 में होंगे राष्ट्रीय वन-खेल प्रतियोगिता

प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन का गवाह होने जा रहा है। इस बार राज्य को राष्ट्रीय वन खेल-कूद प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड वन विभाग तैयारियों में जुट गया है।

प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा, जिसमें देशभर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वन विभागों की टीमें भाग लेंगी। व्यवस्था के लिए विभागीय स्तर पर करीब 10 समितियों का गठन शुरू कर दिया है। आयोजन की भव्यता को देखते हुए वन विभाग ने करीब 20 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसमें देशभर की वन टीमें और राष्ट्रीय संस्थान भाग लेंगे। ■■

चैस प्रतियोगिता में रेनबो पब्लिक स्कूल के आदर्श रहे प्रथम

अंतर्राष्ट्रीय चैस दिवस के अवसर पर रेनबो पब्लिक स्कूल की ओर से विद्यार्थियों की मानसिक अभियोग्यता की अभिवृद्धि के लिए चैस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा नौ के विद्यार्थी आदर्श प्रथम स्थान पर रहे।

इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य डा.रेखा उनियाल ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि चैस जैसे मानसिक खेलों के में भी विद्यालय के विद्यार्थियों ने खासी रुचि दिखाई है और बेहतर प्रदर्शन किया है।

रेनबो पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित चैस प्रतियोगिता में कक्षा नवीं के विद्यार्थी आदर्श ने प्रथम स्थान पाया, तो इसी कक्षा के नैतिक और स्तुति ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि कार्तिक और शौर्य तीसरे स्थान पर रहे।■■

सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया निरीक्षण

रीजनल रिपोर्टर ब्यूरो

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिक्करण की ओर से श्रीनगर के दवा विक्रेताओं को जागरूक किया गया।

इस मौके पर सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम, डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार तथा संयुक्त अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डा.विमल गुसांई की उपस्थिति में दवा विक्रेताओं के साथ गोष्ठी का आयोजन भी किया गया।

श्रीनगर के संयुक्त अस्पताल पहुंची सिविल जज सीनियर डिविजन नाजिश कलीम ने श्रीनगर क्षेत्र के दवा विक्रेताओं से विक्रय की जा रही दवाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित करने के निर्देश दिए। चिकित्सक के परामर्श के मुताबिक ही दवाएं मरीजों को दी जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपभोक्ताओं को भी सजग रहने की जरूरत है। इसके लिए पक्का बिल लेना अनिवार्य है तथा एक्सपायरी तिथि देखकर ही दवाएं खरीदी जानी चाहिए। यदि कोई दवा विक्रेता एक्सपायरी डेट की दवा विक्रय करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर सख्त कार्रवाही की जाएगी।

सेफ ड्रग्स-सेफ लाइफ अभियान के तहत ड्रिस्ट्रिक्ट ड्रग्स इंस्पेक्टर नीरज कुमार की अगुवाई में संयुक्त अस्पताल परिसर में स्थित दो दुकानों का मौके पर ही निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों के रिकॉर्ड खंगाले जाने के साथ ही दुकान मालिकों को यथासंभव निर्देश भी दिए गए। हरेला महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीनगर कोर्ट परिसर पहुंचकर सिविल जज सीनियर डिविजन नाजिश कलीम तथा सिविल जज जूनियर डिविजन अलका ने कोर्ट परिसर में पौधरोपण किया।

इस मौके पर एडवोकेट महेंद्रपाल सिंह सुमन, प्रदीप मैठाणी, प्रमेश जोशी समेत श्रीनगर बार एसोसिएशन के वकील मौजूद रहे। ■■■

26 जुलाई तक समर्थ पोर्टल रहेगा खुला

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त रेनबो कॉलेज ऑफ़ वोकेशनल स्टडीज, बिलकेदार, श्रीनगर (गढ़वाल) में सत्र 2025-26 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल ओपन हो गया है। प्रवेश के लिए 15 जुलाई 2025 से 26 जुलाई 2025 रात्रि 12 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा।

रेनबो कॉलेज ऑफ़ वोकेशनल स्टडीज, बिलकेदार श्रीनगर (गढ़वाल) के निदेशक रिद्धिस उनियाल ने बताया कि योग प्रशिक्षकों के अस्थाई पदों मे भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि राजकीय महाविद्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी तय हुई है। इस योग डिप्लोमा को करके प्रशिक्षक इन योग प्रशिक्षकों की अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भी आवेदन कर सकता है। ■■■

प्रदेश में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति में हुआ बड़ा बदलाव

स्टेट ब्यूरो

उत्तराखंड में अब शिक्षकों के तबादले केवल वरिष्ठता या सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस यानी उनके प्रदर्शन पर तय होंगे। शिक्षा विभाग ने एक नई तबादला नियमावली तैयार कर ली है, जिसमें साफ किया गया है कि यदि कोई शिक्षक लगातार दो साल बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देता है, तो उसे अनिवार्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में तैनाती दी जाएगी।

नए नियम के अनुसार, राज्य को मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में की गई सेवा के लिए गुणांक (अंक) मिलेंगे और इन्हीं अंकों के आधार पर तबादले की पात्रता बनेगी। चार जिले -पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर को उच्च पर्वतीय क्षेत्र माना गया है। जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून के कुछ हिस्सों को निम्न पर्वतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है।

यह पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। तबादलों की शुरुआत हर साल 1 जनवरी से होगी और 31 मार्च तक आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षक को मैदानी या पर्वतीय किसी भी क्षेत्र में कम से कम 5 साल की सेवा देना अनिवार्य होगा।

इस नियमावली में अविवाहित महिला शिक्षक को विवाह के बाद पति के कार्यस्थल या गृह जिले में एक बार तबादले की छूट दी जाएगी। साथ ही, शिक्षकों को पूरे करियर में एक बार संवर्ग परिवर्तन का अवसर मिलेगा, बशर्ते उन्होंने उस संवर्ग में कम से कम 3 साल की सेवा की हो।

नियमावली का एक बार प्रस्तुतिकरण कैबिनेट में हो चुका है। अब कुछ संशोधनों के बाद इसे मंजूरी के लिए फिर से पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद यह नियमावली पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। ■■■

जेल के सामने सुमन पर होगा नाटक

25 जुलाई को टिहरी रियासत के बलिदानी, श्रीदेव सुमन का शहादत दिवस पर नई टिहरी जेल के बाहर 10:30 बजे प्रात: से नाटक होगा।

नाटक में मुख्य भूमिका अंजलि गिरी (सुमन की मां) शिवम गिरी व रुद्रांश पंत (बड़ा व छोटा सुमन) जगजीत नेगी (जेल दरोगा) भगवानचंद रमोला , शिवम पांड्ये, मनीष पंत आदि के साथ निर्देशन अनुराग पंत, सूत्रधार अमित पंत और प्रबंधन डॉ. राकेश भूषण गोदयाल, कमल सिंह महर, देवेंद्र नौडियाल और महिपाल सिंह नेगी का है।■■■

Rainbow college of Vocational Studies

Rainbow college of Vocational Studies

(Affiliated to Sridev Suman Uttrakhand University)

Courses we offer

- Diploma in yoga (Eligibility 12th pass)
- PG Diploma in yoga (Eligibility Graduation pass)
- 1 year diploma in hotel management (eligibility 12th pass)
- 1.5 years diploma in hospitality management (eligibility 12th pass)

Best Courses For Your Careers

100% Placement

देश को मिली पहली योग नीति

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी

विकसित किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को योग पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर स्थापित करना और युवाओं को इससे जोड़ते हुए नए रोजगार अवसर सृजित करना है। राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान में आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए

योग प्रशिक्षकों के अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

राजकीय महाविद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से होगी तैनाती

देहरादून। राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों के 117 अस्थाई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक से आठ अगस्त के बीच अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। इसके बाद 11 अगस्त से चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में तैनाती मिलेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक योग प्रशिक्षकों के

सहमति बनी है।

सेवा योजन विभाग को इन

राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में योग प्रशिक्षकों की तैनाती के लिए दो बार कैबिनेट में प्रस्ताव आ चुका है। पहले 2021 में और फिर 2023 में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो जल्द पूरी की जाए। - **अमित नेगी** प्रांतीय अध्यक्ष योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ

ADMISSION OPEN

REGISTER NOW

riddhishuniyal@gmail.com
www.RCVSUK.IN
+91 7895769152

Bilkedar, Janasu Road
village Arkani, Pauri Garhwal